RAJYA SABHA

Wednesday, the 15th March, 1995/24th Phalguna, 1916 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

OBITUARY REFERENCE

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Members, I refer with profound sorrow to the passing away of Shri Bhupinder Singh, a former Member of the Rajya Sabha.

Shri Bhupinder Singh passed away on the 13th March, 1995 at the age of 85.

Born at Abbottabad in August, 1910, Shri Bhupinder Singh had his education at Abbottabad and Lahore. Shri Bhupinder Singh actively participated in the Indian National Congress in pre-independence days and thereafter in the Akali movement.

A devout Sikh, Shri Bhupinder Singh was the Head Priest of the Golden Temple, Amritsar from 1947 to 1962, and was associated with various Gurdawara Prabandhak Commitees.

Shri Bhupinder Singh was a Member of the Rajya Sabha representing the State of Punjab from April, 1970 to April, 1976 and from October, 1976 to April, 1978.

We deeply mourn the passing away of Shri Bhupinder Singh.

I request Members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed.

(Hon. Members then stood in silence for one minute).

MR. CHAIRMAN: Secretary-General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympahy.

Hon'ble Members yesterday, the question of Bihar was raised by several Members in this House. I have also a notice from the Leader of the Opposition, Shri Sikander Bakht, and from the leader of the Janata Dal, Shri S. Jaipal Reddy, about the same subject and I am glad to inform the House that the Government has informed me that they would make a statement soon after the Question Hour on the subject. Thank you.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

गांवों में दूरसंचार सुविधायें

*41. श्री ईश दत्त यादव: †
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितने गांवों में दूरसंचार सुविधायें उपलब्ध हैं ;

(ख) देश में किन-किन राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक गांवों में दूरसंचार सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ग) 1994–95 के दौरान ऐसे गांवों की संख्या में वृद्धि करने के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 9 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार, देश के 171, 922 ग्रामों में दूरसंचार सुविधायें उपलब्ध हैं।

(ख) 9 मार्च, 1995 तक औसतन लगभग 28.5 प्रतिशत ग्रामों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है। राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात हरियाणा कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु में यह सुविधायें औसत से अधिक उपलब्ध हैं।

(ग) वर्ष 1994–95 के दौरान, ऐसे और 50,000 ग्रामों में यह सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

†सभा में यह प्रश्न श्री ईशदत्त यादव द्वारा पूछा गया।

विवरण

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन का राज्यवार ब्यौरा

क्रम संख्या	सर्किल/ राज्य	आबादी वाले कुल ग्रामों की संख्या	09-3-95 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन	सुविधा प्राप्त क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	29341	20326	69.30%
2	असम	20454	5588	27.00%
3.	बिहार	79208	10508	13.30%
4	गुजरात (दादर तथा नगर हवेली, दमण, दीव सहित)	18735	11696	62.00%
5.	हरियाणा	7190	6140	85.40%
6	हिमाचल प्रदेश	16997	2698	15.90%
7.	जम्मू तथा कश्मीर	6447	1172	18.20%
8.	कर्नाटक	27024	8142	30.00%
9.	केरल	1530	1524	99.70%
10.	मध्य प्रदेश	71386	22660	31.80%
11	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	36187	16858	46.60%
12.	उत्तर पूर्व (मिजोरम, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर)	15192	1815	11.90%
13.	उड़ीसा	51057	7616	14.90%
14.	पंजाब	13252	8120	61.00%
15.	राजस्थान	37889	8922	23.50%
16.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	15826	12554	79.00%
17.	उत्तर प्रदेश	112568	21125	18.80%
18.	पश्चिमी बंगाल (सिक्किम तथा अंडमान एवं निकोबार सहित)	43306	4458	10.30%
	योग	603594	171922	28.50%

श्री ईश दत्त यादव : मान्यवर सभापति जी, देश के आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय समन्वित विकास के लिए पूरे देश को गांवों के स्तर तक टेलीफोन कनेक्शन से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है और संभवतः सरकार ने भी इसको महसूस किया था लेकिन सरकार अपने इस कार्यक्रम में पूर्णतया असफल हो गई है क्योंकि माननीय संचार मंत्री जी ने आज उत्तर दिया है, इस उत्तर से यह स्पष्ट है मान्यवर, कि 9-3-95 तक केवल 1,71,922 ग्रामों में ही टेलीफोन कनेक्शन दे सके हैं जो 28.5 प्रतिशत है और देश के अन्य सभी गांव इस टेलीफोन कनेक्शन की सेवा से वंचित रह गये हैं। मान्यवर, सन् 1993 में संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग की प्राक्कलन समिति ने दूरसंचार विभाग से एक स्पष्टीकरण चाहा था और यह प्रतिवेदन इस समिति ने लोक सभा में प्रस्तुत किया था। इस प्रतिवेदन को देखने से स्पष्ट है कि उस समय दूरसंचार विभाग ने और संचार मंत्रालय ने समिति को यह आश्वासन दिया था कि सभी ग्राम पंचायतों को 1-4-95 तक फोन सुविधा प्रदान कर दी जाएगी और अब केवल 17 दिन रह गये हैं परन्तु अब तक केवल 28.5 गांवों में ही यह सुविधा पहुंची है दूसरा उन्होंने आश्वासन दिया था . . .

श्री चतुरानन मिश्र : इसी शताब्दी तक या अगली ? 1995 तक या 20 सौ तक . . . ?

श्री ईश दत्त यादव: 1995 तक। तो उप मण्डल मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों और समतुल्य नगरों, जहां 500 लाइन या इससे अधिक क्षमता के एक्सचेंज हैं, उनको भी 1-4-95 तक एन.एस.डी. सुविधा प्रदान कर दी जाएगी और सभी मैनुअल एक्सचेंजों को बदलकर 1994 तक ही पूर्ण संचालित कर दिया जाएगा, यह आश्वासन दिया गया था। तो आपके द्वारा इस प्रकार की शिथिलता क्यों बरती गयी है और आप इस लक्ष्य को कब तक पूरा कर सकेंगे क्योंकि अभी तक आपने केवल 28.5 प्रतिशत ग्रामों में ही टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करायी है। तो बाकी जो गांव बचे हैं, उनके लिए आपकी क्या कार्य योजना है और इन ग्रामों को कब तक टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी ? यह उत्तर मैं चाहता था और इस संबंध में आपका आश्वासन भी चाहता था।

श्री सुखराम : चेयरमैन महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि दूरभाष, टेली कम्यूनिकेशन आज समाज की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण आधार है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय यह बात तया की गयी थी कि 1-4-95 तक सभी ग्राम पंचायतें, जो 2 लाख 36 हजार 218 हैं, उनमें यह सुविधायें प्रदान की जाएंगी। मैं यह बात मानता हूं कि यह सुविधा सभी ग्राम पंचायतों में अभी तक प्रदान नहीं की गयी। उसकी एक वजह तो यह है कि पुरानी टैक्नॉलाजी जो वायर बेस थी, उसको अब हमने रेडियो टेक्नॉलाजी पर लाने की कोशिश की है और उसकी वजह से यह जो इक्विपमेंट है, एम.ए.आर.आर., जो हमारे देश में मैनुफैक्चर नहीं होते थे, अब मैनुफैक्चर होने लगे हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। क्योंकि एक दफा मेज़ कम्पनी ने कुछ मुनैफैक्चर किए, उनको लगाया और उनकी वजह से ग्राम पंचायतों को बहुत परेशानी हुई। उसको बदल दिया गया और अभी हम नये लगा रहे हैं। इस वजह से भी देर हुई है। अभी जो हमारी राष्ट्रीय टेली कम्युनिकेशन की नीति मई महीने में पास की, उसमें हमने इस बात का निर्णय लिया है कि 1997, जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष है, उसमें न सिर्फ ग्राम पंचायतों बल्कि जो हमारे 6 लाख 3 हजार गांव सारे देश में हैं, उन सभी में दूरभाष की, टेली कम्युनिक्शन की सुविधा दी जाएंगी। मैं इस बात को मानता हूं कि हमने इस बात का आश्वासन दिया था मगर मैंने यह तय किया कि बजाय इसके कि हम नम्बर गैम पर चलें, क्वालिटी जिसके संबंध में माननीय सदस्यों को हमेशा चिंता लगी रहती है, उस पर ध्यान दिया जाए। गांव में हम यह सुविधायें देते हैं मगर वह काम नहीं करती तो परेशानी होती है

इसलिए मैंने तय किया कि क्वालिटी हमें एक्योर करनी है। जो इक्युमेंट लगाने की बात है उसके लिए हमारी कोशिश है। मैं मानता हूं 1995 तक नहीं हो सकता लेकिन 1997 तक सारे ग्राम पंचायतों में होगा, यह मैंने आप से पहले भी निवेदन किया है। दूसरे, जो मैंने आश्वासन दिया था कि 1994 के अंत तक जितने मैनुअल एक्सचेंज हैं वे सारे खत्म हो जायेंगे वह आश्वासन पूरा किया है। आज देश में कोई भी मैनुअल एक्सचेंज नहीं है। हमारी जो नई नीति है उसके तहत प्राइवेट सेक्टर आ रहा है। उस प्राइवेट सेक्टर के लिए हमने टेंडर में ही इस बात को तय किया है कि दस प्रतिशत गांवों में टेलीफोन देना आवश्यक होगा और मैंने इस बात को भी कहा है कि उन लोगों को वेटेज दिया जायेगा जो गांवों में ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत देंगे। मुझे विश्वास है आने वाले दो वर्षों में पूरे देश में सभी गांवों में, हमने तो यह कहा था ग्राम पंचायत में एक पी.सी.ओ. देंगे लेकिन अब गांव में जितनी आवश्यकता होगी वह दो साल में पूरी करेंगे।

श्री ईश दत्त यादव: मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि कुछ राज्यों में तो गांवों में जो टेलीफोन कनेक्शन दिये हैं उनकी प्रगति ठीक है लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो आपने आंकड़े दिये हैं प्रदेशवार उनके हिसाब से बिहार में 13.30 प्रतिशत, उड़ीसा में 14.90 प्रतिशत, नागालैंड और मिजोरम में 11 प्रतिशत ही टेलीफोन दिये गये हैं, इसका क्या कारण है? आपके विभाग ने इसमें लापरवाही क्यों की? अगर आपके विभाग ने लापरवाही की तो आपने उसमें क्या एक्शन लिया और उन पर क्या कार्रवाई की? पार्ट-बी मेरा प्रश्न यह होगा कि अब तक जिन गांवों में टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं वे अधिकांश डैड रहते हैं, काम नहीं कर रहे हैं। वे एक्सचेंज एकदम असफल हो गये हैं। कुछ लोग जो बड़े लोग हैं उन गांवों में वे व्यावसायिक दृष्टि से सड़कों पर टेलीफोन लगवा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि गांवों में जो टेलीफोन लगे हैं उनमें 80 प्रतिशत टोटल फेल हो गये हैं।

MR. CHAIRMAN: Please put your question? Already 15 minutes are over. Will you please conclude?

श्री ईश दत्त यादव: मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि गांवों में जो टेलीफोन लगे हुए हैं उनमें 80 प्रतिशत टेलीफोन काम नहीं कर रहे और कुछ टेलीफोन गांव के बड़े लोगों ने व्यावसायिक दृष्टि से सड़कों पर ले लिये हैं और गांव के नाम पर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं? अगर मंत्री महोदय को इस तरह की जानकारी है तो इसमें आपने क्या कार्रवाई की और दूसरे जो खराब पड़े हैं उनको सही कराने के लिए आपका विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है?

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: उत्तर प्रदेश में औसत से भी कम है।

श्री सुख राम: मैं मानता हूं कुछ राज्यों में जो औसत है उससे बहुत ज्यादा है। जैसे हरियाणा में 85 प्रतिशत है, गुजरात में 62 प्रतिशत है, आन्ध्र प्रदेश में 69, 70 प्रतिशत है। कुछ राज्यों में जैसे बिहार है उसमें बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में, नार्थ ईस्ट प्रदेशों में आप जानते हैं वहां पर ला एण्ड आर्डर की सिच्युएशन कैसी है, उसकी वजह से भी और लोकेशन की वजह से भी वहां कम है। आप इस बात का विश्वास रखिये कि जो हो गया सो हो गया। हमारी जो नीतियां हैं और जो प्लानिंग है उसमें कुछ अंतर हो सकता है। इक्युपमैंट समय पर नहीं पहुंचे उसकी वजह से भी हो सकता है। इस बात को देखते हुए मैंने सभी सर्किल से एक बात कही है कि जहां-जहां जिस-जिस राज्य में प्रतिशत कम है उसमें प्राथमिकता दी जाये। बाकियों का काम बंद नहीं होगा, वह भी काम आगे बढ़ेगा लेकिन जो पीछे रह गये हैं उनको प्राथमिकता देनी है। जो आपने कहा है कि गांवों में 80 प्रतिशत खराब हैं मेरे पास इसका ब्यौरा नहीं है। मेरा माननीय सदस्यों से एक निवेदन है।

हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि मेस की कंपनी ने जो दो-ढ़ाई साल पहले सप्लाई किए थे, वे खराब निकले और वह चल नहीं सके। इसकी वजह से परेशानी हो गयी। हमने उनको बंद कर दिया है और उनको रिप्लेस कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि जहां-जहां आपकी जानकारी में आए कि यहां यहां खराबी है तो आप उसको मुझे बतलाइए। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि उनको मैं ठीक कराऊंगा। हो सकता है कि गांवों में बहुत जगह शिकायतें हों, मगर 80 प्रतिशत है, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं (**व्यवधान**)

श्री ईश दत्त यादव : आप इसकी स्वयं जांच करा लीजिए।

श्री सुखराम : मैं देखूंगा कि इसमें क्या हो सकता है ?

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : आप जिनको किताबों में देखते हैं, लाग बुक में देखते हैं, उनको तो ठीक करवा लीजिए। वास्तव में गांवों में जो हालत है वह इससे भी बदतर है। उन्होंने 80 प्रतिशत कहा। इसको आप चेकअप करायें कि कागजों में क्या होता है और क्या प्रैक्टिस में है ?

श्री सुखराम : मेरे लिए विभाग की सूचना से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी सूचना है।

श्री दिग्विजय सिंह : : हमने आपको सूचना भेजी, दस चिठियां लिखी लेकिन कुछ काम नहीं हुआ।

Sir I have written 10 letters.

चौधरी हरमोहन सिंह : सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और वहां पर 18.80 प्रतिशत ही दूर संचार की व्यवस्था है जब कि छोटे प्रदेशों में यह 85 प्रतिशत से भी अधिक है। इस दूरी को कम करने के लिए आप क्या विचार कर रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं ?

श्री सुखराम : सभापति जी, उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ा प्रदेश है। मैंने, इस बात से कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा काम हो, इसके लिए एक बड़े महत्व का फैसला लिया है। हमने उत्तर प्रदेश में एक सर्कल और बना लिया है जिसकी वजह से वहां दो सर्कल हो गए हैं। इससे मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष से जब यह दूसरा सर्कल काम करना शुरू करेगा तो उत्तर प्रदेश में जो कमी रह गयी है वह कमी आइंदा आने वाले समय में पूरी हो जाएगी।

चौधरी हरमोहन सिंह : कब तक पूरी करेंगे ?

श्री सुखराम : मैंने आपको कहा कि इस साल से दूसरा सर्कल फंक्शन करना शुरू कर देगा।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : वह शुरू हो गया है, देहरादून में और दूसरा लखनऊ में है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है।

SHRI DAVID LEDGER: Mr. Chairman, Sir, after going through the reply given by the hon. Minister it becomes clear that there is a wide disparity, as my hon. friend has just mentioned, in the percentage of coverage of villages under the scheme between one State and the other. We find that, in Kerala, the percentage of coverage is almost cent per cent. It is 99.70 per cent, while in West Bengal, Sikkim and Andaman and Nicobar it is 10 per cent, in the North-East it is 11 per cent and in Bihar it is 13.30 per cent. The hon. Minister has tried to explain it away by saying that in the North-East there is a law and order problem which is not at all acceptable to me. I would

like to know the exact reason for this disparity. This is part (a) of my question. Part (b) of my question is, what immediate programme does the Ministry propose to take up to reduce this disparity and to include more and more villages in the States under these programmes?

SHRI SUKH RAM: Sir, I have already replied to it. Anyway, I will still make it clear that it might be due to defective policies on account of which priority was not given to certain States or it might be due to non-supply of the equipment well in time. That is why some States lagged behind. I have already assured this hon. House that I would see to it that those States which are lagging behind in telecommunication facilities will be given priority. I again assure the House that within the next two years by 1997, not only Gram Panchayats but also all villages numbering 6,03,000 will be provided telecom facilities.

Our policy has been to provide telecom facility not only to Grampan*chayats;* all those villages which want telecom facility will be provided with it.

श्री राघवजी : सभापति जी, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए टेलीफोन सुविधाओं की बहुत आवश्यकता होती है। हिन्दुस्तान में अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों की जनसंख्या का एक चौथाई से अधिक भाग मध्य प्रदेश में रहता है और मध्य प्रदेश में केवल 21 प्रतिशत गांवों में टेलीफोन सुविधाएँ उपलब्ध हो सकी हैं प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत को देखते हुए मध्य प्रदेश के आदिवासियों क्षेत्रों के विकास के लिए और पूरे देश के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए क्या मंत्री जी विशेष कार्य योजना बना कर इन क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधायें प्रदान करेंगे ? जिन गांवों में अनुसूचित जनजाति के लोग अधिक रहते हैं, क्या उन गांवों में टेलीफोन लगाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी ?

श्री सुखराम : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश क्षेत्र के हिसाब से हिन्दुस्तान में सब से बड़ा प्रदेश है। वहां गावों की संख्या भी काफी ज्यादा है। यह भी मैं मानता हूं कि जो पूरे देश का एवरेज है, उसके मुकाबले में मध्य प्रदेश टेलीफोन सुविधाओं में थोड़ा आगे तो है। जहां तक जनजातीय लोगों का प्रश्न है, ऐसे क्षेत्रों का प्रश्न है, हमारी नीति में हमने इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी हुई है और जनजातीय क्षेत्रों को टेलीफोन प्रदान करने में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। आने वाले समय में, जैसे मैंने अभी कहा कि मध्य प्रदेश में भी बाकी प्रदेशों के साथ साथ तेजी से काम होगा। अब तो प्राइवेट सेक्टर इस वर्ष में करीब सितम्बर–अक्तूबर मास तक आने वाला है। हमारा विभाग तो बहुत बड़ा काम कर ही रहा है लेकिन प्राइवेट सेक्टर के आने से सारे देश की जो आवश्यकता टेलीफोन के क्षेत्र में है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में आने वाला है।

श्री संघ प्रिय गौतम : इन का स्पेसेफिक क्वेश्चन था कि वहां पर कितने का टारगेट आपने अनाऊंस किया है ?

श्री राघवजी : अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को आप प्राथमिकता देंगे अथवा नहीं, केवल इतना बता दीजिए ?

श्री सुखराम : मैंने कहा है कि देंगे।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे : सभापति महोदय, महाराष्ट्र और गोआ दोनों का बैकलॉग है और 43 प्रतिशत वहां अभी काम हुआ है। दो सालों में आप काम करने वाले हैं और सभी देहातों में आपने टेलीफोन सुविधायें देने के लिए तया किया है। महोदय, हमारे मंत्री जी हिमाचल प्रदेश से आते हैं वहां पर 84 प्रतिशत का बैकलॉग है। क्या दोनों राज्यों में 50 प्रतिशत काम इस साल में कंपलीट करने के लिए आप डायरेक्शन दे सकेंगे ? हिमाचल प्रदेश और महराष्ट्र में... **(व्यवधान)**

श्री दिग्विजय सिंह : बाकी राज्यों को क्यों छोड़ रहे हैं ? यह तो रीजनल इंबेलेंस **(व्यवधान)**

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे : हिमाचल प्रदेश का मैं विशेष रूप से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे कई साथ गर्मी से बचने के लिए ठंडा होने के लिए हिमाचल प्रदेश में जाते हैं। इसलिए मैं यह कहता हूं कि उन लोगों को अपने क्षेत्र के लोगों से कंटेक्ट करने की सुविधा वहां से मिल सके **(व्यवधान)** ठीक है, मेरे पास तो 14 राज्य हैं लेकिन मैं विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए पूछना चाहूंगा क्योंकि मंत्री जी खुद उस स्टेट से आते हैं, फिर भी इतना बड़ा बैक्लॉग वहां है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि महाराष्ट्र में काफी खेती करने वाले जो लोग हैं हर देहात में टेलीफोन मांग रहे हैं। वहां अगर 20 हजार विलेजेज का बैक्लॉग है तो वहां क्या आप इस साल 10 हजार को टेलीफोन सुविधा दे देंगे और इसी प्रकार से 50 प्रतिशत काम हिमाचल प्रदेश में कर देंगे और बाकी 50 प्रतिशत काम अगले साल में कर देंगे तो इससे अगले दो साल में सारा काम कंपलीट हो सकेगा। मैं आपसे इतना स्पष्ट रूप से आश्वासन चाहता हूं।

श्री सुखराम : सभापति जी, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की ओर विशेष ध्यान दिलाने की कोशिश की है। मैं माननीय सदन से एक बात का निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले करीब तीन वर्षों से इस मंत्रालय को कोई बजटरी सपोर्ट नहीं मिली है। जो हमारा रेवेन्यू है, वह अभी जो इन्फास्ट्रक्चर है उसमें हम जनरेट करते हैं। उस रेवेन्यू से एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, मेन्टिनेंस भी कर रहे हैं और गांवों में एक टेलीफोन के पीछे हमें एक लाख बीस हजार-पच्चीस हजार की सब्सिडी देनी पड़ती है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए .. **(व्यवधान)** मेरी बात तो सुन लीजिए .. **(व्यवधान)**

श्री दिग्विजय सिंह : सुनते सुनते आधा घंटा हो गया। हम लोग मोटा-मोटी यह बात कहना चाहते हैं कि आपका नेशनल एवरेज 28 परसेंट है। दूसरी जगह डेवलपमेंट का काम तब तक नहीं होगा जब यह एवरेज पूरा न हो। इसका एश्योरेंस हमें दीजिए .. **(व्यवधान)** 28 परसेंट का जो एवरेज है यह तो कहिए कि 28 परसेंट का एवरेज जब पूरा होगा तभी दूसरी जगह लगेंगे। 12–13 परसेंट की नेशनल डिसपैरिटी है ... **(व्यवधान)**

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे : उत्तर प्रदेश के होकर हमारे ऊपर अन्याय मत कीजिए।

श्री मोहम्मद सलीम : दो मिनट की बात 20 मिनट में कहते हैं।

†[شری محمد سلیم : در ملت
ی. یا ۲۰ ملت میں کہتے ہیں۔ ع.]

MR. CHAIRMAN: Let the Minister answer.

श्री सुखराम : क्वेश्चन इनका है और इन्टरप्शन ये कर रहे हैं .. **(व्यवधान)**

मैंने आप से यह निवेदन किया कि धन के अभाव की वजह से जितनी आशा है सभी माननीय सदस्य को गांवों के बारे में वह हम पूरी नहीं कर सके। पर मैंने आपको इस बात का आश्वासन पहले भी दिया और अब भी आश्वासन देना चाहूंगा कि जिन स्टेटों में अभी बैक्लॉग है, पीछे हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी-महाराष्ट्र में भी। हिमाचल का आप ने, माननीय सदस्य ने अच्छा किया कि ध्यान दिला दिया। हिमाचल भी पीछे है कोई ऐसी बात नहीं है जो यहां माननीय सदस्य कहते हैं कि मेरी होम स्टेट है इस वास्ते मैंने हिमाचल को प्राथमिकता दी है। हिमाचल भी आपके साथ ही चल रहा है आप चिंता मत करिए।

Foreign assistance for lapping ONGC's well fire

*42. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: †

SHRI GHUFRAN AZAM:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Krishna Kumar Birla.